

पत्रावली पेज हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण एकपक्षीय। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि का बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी की कब्जाहुदा भूमि में विप्रार्थी आए दिन दंखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते हैं तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू हैं, यदि इसमें सफल हो गए तो प्रार्थी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतं प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश से विप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि के प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 9 सहखातेदार हैं तथा सहखातेदाना के रिकॉर्ड में हिस्से भी खुले हुए हैं। प्रार्थी/वादी का मूलवाद साक्ष्य गवाहान में विचाराधीन चल रहा है। ऐसी सूरत में इस स्तर पर स्थगन से सहखातेदारान को पाबंद नहीं किया जाता सकता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम दृश्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) जालोतरा